भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1424

15 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

अमृत योजना का कार्यान्वयन

1424. श्री सुनील कुमार सोनी:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

डॉ. मनोज राजोरिया:

श्री विजय बघेल:

श्री दिलीप शइकीया:

श्री अरूण साव:

श्रीमती रंजीता कोली:

श्री पी.सी.मोहन:

डॉ.लोरहो फोज:

श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, कर्नाटक, झारखंड और मणिपुर में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कार्यान्वयन की जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त राज्यों में कितने शहरों का चयन किया गया है और चयन के तत्संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में योजना के अंतर्गत आवंटित और खर्च की गई निधियों का वर्ष और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क): 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। यह मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; हरे-भरे स्थान और पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन में शहरी सुधारों और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मंजूरी दे दी है जिसमें 35,990 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (सीए) सहित संपूर्ण मिशन अवधि के लिए 77,640 करोड़ रुपये शामिल है। अब तक, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 82,222 करोड़ रूपये लागत वाली 5,873 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 32,793 करोड़ रूपये की लागत वाली 4,676 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, 49,430 करोड़ रूपये की लागत वाली 1,197 परियोजनाओं के लिए संविदाएं की जा चुकी हैं और ये परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, लगभग 66,313 करोड़ रुपये के समग्र कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं और 59,615 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

परियोजनाओं के लिए 35,990 रुपये के केंद्रीय हिस्से में से अब तक 31,198 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अमृत के विभिन्न घटकों जैसे परियोजनाएं, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय, सुधारों को प्रोत्साहन, पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की परियोजनाओं और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) स्थानीय क्षेत्र योजना और नगर नियोजन योजना (एलएपी-टीपीएस) की उप योजनाओं के तहत कुल मिलाकर 37,533 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

अब तक, क्रमश: लक्षित 139 लाख नल कनेक्शनों और 145 लाख सीवर कनेक्शनों में से अमृत योजना और अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 134 लाख नल कनेक्शन और 102 लाख सीवर कनेक्शन (मल और सेप्टेज प्रबंधन - एफएसएसएम के माध्यम से कवर किए गए घरों सहित) प्रदान किए गए हैं।

अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,340 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की कुल सीवेज शोधन क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें से 2,840 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है और 1,437 एमएलडी क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित की जा चुकी है।

अमृत के तहत 2,299 हरित पार्कों का विकास किया गया है जिससे 4,480-एकड़ के हरित स्थानों की वृद्दि हुई है। इसके अतिरिक्त, चल रही पार्क परियोजनाओं के माध्यम से 951 एकड़ के भू-भाग को हरित स्थान में परिवर्तित किया जाएगा।

अमृत के तहत 666 वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके परिणामस्वरूप 2,434 जल भराव वाले स्थानों को दुरूस्त कर दिया गया है और अन्य 1,307 जल भराव बिंदुओं को दुरूस्त करने का कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण के अनुकूल परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 250 से अधिक ग्रीन मोबिलिटी परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

<u>अमृत के सुधार घटक की उपलब्धियां:</u>

शहरी सुधार अमृत के तहत एक मुख्य एजेंडा है, जो 54 उपलब्धियों के साथ 11 सुधारों का एक सेट है। सुधार कार्यान्वयन के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन के रूप में 1,884.86 करोड़ रूपये प्रदान किए गए हैं।

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, चिन्हित की गई 101 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों में से 97 लाख को ऊर्जा कुशल एलईडी से बदल दिया गया है, जिससे प्रति वर्ष 212 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है और CO2 उत्सर्जन में प्रति वर्ष 16.93 लाख टन की कमी आई है।

शहरों को क्रेडिट योग्य बनाने के लिए 470 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा कर लिया गया है। 164 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग (आईजीआर) प्राप्त हुई है, जिनमें A- या उससे ऊपर की रेटिंग वाले 36 शहर शामिल हैं।

11 शहरी स्थानीय निकायों अर्थात अहमदाबाद, अमरावती (आंध्र प्रदेश), भोपाल, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ पुणे, सूरत, वड़ोदरा और विशाखापत्तनम द्वारा नगरपालिका बांड के माध्यम से 3,940 करोड़ रूपये जुटाए गए हैं। बांड जारी करने के लिए इन शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन के रूप में 227 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

भवन निर्माण अनुमति ऑनलाइन जारी करने की सुविधा के लिए 457 अमृत शहरों सहित 2,465 शहरों में ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) शुरू कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 में निर्माण अनुमति के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में भारत की रैंक वर्ष 2018 की रैंक 181 के मुकाबले सुधर कर 27 हो गई है।

461 अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति कर, पानी और सीवेज कवरेज आदि जैसी विभिन्न स्तरों के माध्यम से कुशल शहरी प्रशासन प्राप्त होगा। 148 शहरों के लिए अंतिम योजना तैयार की जा चुकी है और अन्य 135 शहरों के लिए मसौदा योजना तैयार है।

भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने और शहरी फैलाव को रोकने के लिए शहरी नियोजन में राज्यों/शहरों की क्षमता में सुधार करने के लिए, 25 शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना और नगर नियोजन योजना (एलएपी-टीपीएस) के कार्यान्वयन पर प्रायोगिक योजना शुरू की गई है। इनमें से 12 शहरों ने अपना एलएपी-टीपीएस मसौदा पूरा कर लिया है।

अमृत के तहत छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, कर्नाटक, झारखंड और मणिपुर में शुरू की गई परियोजनाओं का जिलेवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, कर्नाटक, झारखंड और मणिपुर राज्य में चयनित शहरों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ शहरों की संख्या: 9				
अम्बिकापुर	भिलाई नगर	बिलासपुर	दुर्ग	जगदलपुर
कोरबा	रायगढ़	रायपुर	राजनंदगांव	

राज्य का नाम: राजस्थान शहरों की संख्या: 29				
अजमेर	भिवाड़ी	गंगानगर	जोधपुर	सीकर
अलवर	बीकानेर	गंगापुर सिटी	किशनगढ़	सुजानगढ़
बरन	बूंदी	हनुमानगढ़	कोटा	टोंक
ब्यावर	चितौड़गढ़	हिण्डौन	नागौर	उदयपुर
भरतपुर	चुरू	जयपुर	पाली	झालावाड़
भीलवाड़ा	धौलपुर	झुंझुनूं	सवाई माधोपुर	

राज्य का नाम: असम शहरों की संख्या: 4			
डिब्रूगढ़	गुवाहाटी	नौगांव	सिलचर

राज्य का नाम: कर्नाटक शहरों की संख्या: 27				
बागलकोट	बीजापुर	गंगावती	कोलार	रानीबेन्नूर
बीबीएमपी	चिकमंगलूर	गुलबर्गा	मंड्या	रॉबर्टसन पेट
बेलगाम	चित्रदुर्ग	हसन	मंगलौर	शिमोगा
बेल्लारी	दावनगेरे	होसपेट	मैसूर	तुमकुर
भद्रावती	गडग-बेटिगेरी	हुबली, धारवाड़	रायचूर	उडुपी
बीदर	बादामी			

राज्य का नाम: झारखंड शहरों की संख्या: 7				
आदित्यपुर	चास	देवघर	धनबाद	गिरिडीह
हजारीबाग	रांची			

राज्य का नाम: मणिपुर शहरों की संख्या: 1
इंफाल

इसके अतिरिक्त, देश भर में अमृत के तहत शहरों / कस्बों का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया है :

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सभी राजधानी शहर/नगर
- छावनी बोर्डों में नागरिक क्षेत्रों सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर और कस्बे
- राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय) के तहत विरासत शहर के रूप में वर्गीकृत सभी शहर / कस्बे
- 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले मुख्य नदियों के किनारे वाले तेरह शहर और कस्बे, और
- पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)।

(ग): अमृत के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) -वार धनराशि जारी की जाती है, न कि जिले-वार।

अमृत के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (सीए) का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

"अमृत योजना के कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1424 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर और राजस्थान में अमृत परियोजनाओं की स्थिति

राज्य	शहर	जिला जिसमें शहर है	कार्य पूरा हो गया है		जारी है		कुल	
			संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
असम	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	4	3.98	2	193.93	6	197.91
	गुवाहाटी	कामरूप			3	5.11	3	5.11
	नगांव	नगांव	3	3.59	1	238.33	4	241.92
	सिलचर	कछार	3	3.3	1	177.47	4	180.77
असम कुल			10	10.87	7	614.84	17	625.71
छत्तीसगढ	अम्बिकापुर	सरगुजा	33	105.29	1	0.07	34	105.36
	भिलाई नगर	दुर्ग	46	140.24	4	87.06	50	227.3
	बिलासपुर	बिलासपुर	14	114.68	5	191.36	19	306.04
	दुर्ग	दुर्ग	20	44.34	5	118.72	25	163.06
	जगदलपुर	बस्तर	33	82.63	9	75.55	42	158.18
	कोरबा	कोरबा	27	207.1	2	10.48	29	217.58
	रायगढ़	रायगढ़	20	191.21	2	1.24	22	192.45
	रायपुर	रायपुर	27	97.48	8	575.7	35	673.18
	राजनंदगांव	राजनंदगांव	34	71.83	3	154.52	37	226.35
छत्तीसगढ़ कुल			254	1054.8	39	1214.7	293	2269.5
झारखंड	आदित्यपुर	सरायकेला-खरसावां	7	56.72	6	491.69	13	548.41
	चास	बोकारो	6	20.18	4	122.08	10	142.26
	देवघर	देवघर	5	4.01	1	9.97	6	13.98
	धनबाद	धनबाद	5	5	1	159.31	6	164.31
	गिरिडीह	गिरिडीह	7	46.18			7	46.18
	हजारीबाग	हजारीबाग	6	34	3	394.41	9	428.41
	रांची	रांची	6	54.81	2	216.7	8	271.51
झारखंड कुल			42	220.9	17	1394.16	59	1615.06
कर्नाटक	बादामी	बागलकोट	10	36.06			10	36.06
	बागलकोट	बागलकोट	28	49.91	2	67.54	30	117.45
	बीबीएमपी	बेंगलुरु शहरी	23	713.09	3	278.86	26	991.95
	बेलगाम	बेलगाम	4	21.55	1	162.73	5	184.28
	बेल्लारी	बेल्लारी	4	99.79	2	93.62	6	193.41
	भद्रावती	शिमोगा	1 1	152.34	1	1.04	12	153.38
	बीदर	बीदर	5	110.76	3	76.09	8	186.85
	बीजापुर	बीजापुर	7	25.09	1	174.04	8	199.13
	चिकमंगलूर	चिकमंगलूर	8	9.83	3	117.27	1 1	127.1
	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	14	62.38	1	66.4	15	128.78
	दावनगेरे	दावनगेरे	9	4.82	1	174.96	10	179.78
	गडग-बेटिगेरी	गदग	17	177.45	2	18.61	19	196.06
	गंगावती	कोप्पल	20	96.07	2	14.13	22	110.2
	गुलबर्गा	गुलबर्गा	7	190.59			7	190.59

राज्य	शहर	जिला जिसमें शहर है	कार्य पूरा हो गया है		जारी है		कुल	
			संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
	हसन	हसन	7	25.03	1	114.68	8	139.71
	होसपेट	बेल्लारी	1 1	102.86	4	70.17	15	173.03
	हुबली, धारवाड़	हुबली, धारवाड़	4	177.07			4	177.07
	कोलार	कोलार	31	52.46	5	78.51	36	130.97
	मंड्या	मंड्या	10	138.81			10	138.81
	मंगलौर	दक्षिण कन्नड़	6	65.23	3	135.98	9	201.21
	मैसूर	मैसूर	8	89.59	1	102.44	9	192.03
	रायचुर	रायचुर	10	166.09	1	9.06	1 1	175.15
	रानीबेन्नूर	हावेरी	1 1	147.47			1 1	147.47
	रॉबर्टसन पेट	कोलार	27	86.98	7	64.33	34	151.31
	शिमोगा	शिमोगा	25	136.95	4	36.08	29	173.03
	तुमकुर	तुमकुर	35	176.57	1	18.04	36	194.61
	उडुपी	उडुपी	4	0.98	2	128.55	6	129.53
कर्नाटक कुल			356	3115.82	51	2003.13	407	5118.95
मणिपुर	इंफाल	इंफाल	1	1.28	5	210.59	6	211.87
मणिपुर कुल			1	1.28	5	210.59	6	211.87
राजस्थान	अजमेर	अजमेर	4	31.13	1	74.77	5	105.9
	अलवर	अलवर	4	83.81	2	86.8	6	170.61
	बरन	बरन	1	1	6	167.17	7	168.17
	ब्यावर	अजमेर	6	153.02			6	153.02
	भरतपुर	भरतपुर	4	51.27	1	88.48	5	139.75
	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1	9.95	2	23.52	3	33.47
	भिवाड़ी	अलवर	3	2.06	2	133.76	5	135.82
	बीकानेर	बीकानेर	4	35.67	1	123.78	5	159.45
	बूंदी	बूंदी	4	101.23	1	47.71	5	148.94
	चितौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	5	56.48	1	87.78	6	144.26
	चुरू	चुरू	5	24.46	1	64.2	6	88.66
	धौलपुर	धौलपुर	3	1.01	3	59.17	6	60.18
	गंगानगर	सवाई माधोपुर	3	1.16	1	2.38	4	3.54
	गंगापुर सिटी	हनुमानगढ़	3	1.25	3	167.23	6	168.48
	हनुमानगढ़	करौली	4	9.37			4	9.37
	हिण्डौन	जयपुर	3	2.5	2	118.15	5	120.65
	जयपुर	झालावाड़	5	34.21	2	94.08	7	128.29
	झालावाड़	झुंझुंनू	2	2.5	1	68.66	3	71.16
	झुंझुनूं	जोधपुर	4	8.28			4	8.28
	जोधपुर	अजमेर	5	35.41	2	21.88	7	57.29
	किशनगढ़	कोटा	4	112.19			4	112.19
	कोटा	नागौर	5	71.34	4	227.58	9	298.92
	नागौर	पाली	2	1.12	2	100	4	101.12
	पाली	सवाई माधोपुर	4	11.8			4	11.8
	सवाई माधोपुर	सीकर	3	74.92			3	74.92
	सीकर	श्री गंगानगर	5	135.8	1	74.28	6	210.08

राज्य	शहर	जिला जिसमें शहर है	कार्य पूरा हो गया है		जारी है		कुल	
			संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)	संख्या	राशि (करोड़ में)
	सुजानगढ़	चुरू	4	11.17	1	104.07	5	115.24
	टोंक	टोंक	2	1.85			2	1.85
	उदयपुर	उदयपुर	4	82.19	2	104.53	6	186.72
राजस्थान कुल			106	1148.15	42	2039.98	148	3188.13

"अमृत योजना के कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1424 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अमृत योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्योरा:

अमृत के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता	परियोजनाओं के लिए					अन्य घटकों के लिए				
			वित्तीय वर्ष: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	वर्तमान वित्तीय वर्ष: 2022-23	कुल	वित्तीय वर्ष: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	चालू वित्तीय वर्ष: 2022-23	कुल
1	असम	591.42	-	-	179.64	-	179.64	10.42	6.12	-	-	16.54
2	छत्तीसगढ	1,009.74	145.67	415.55	-	-	561.22	15.91	17.52	3.89	-	37.31
3	झारखंड	566.17	135.22	109.62	109.62	-	354.46	6.78	0.40	2.36	-	9.54
4	कर्नाटक	2,318.79	710.54	280.50	125.93	-	1,116.97	52.00	18.74	9.14	-	79.88
5	मणिपुर	162.28	-	66.06	-	-	66.06	1.46	0.30	0.15	-	1.92
6	राजस्थान	1,541.95	143.91	586.54	-	-	730.45	11.13	16.73	-	1.75	29.61
कुल		6,190.35	1,135.34	1,458.27	415.19	-	3,008.80	97.70	59.81	15.55	1.75	174.81

अमृत के तहत जारी केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	परियोजनाओं के लिए					अन्य घटकों के लिए				
		वित्तीय वर्ष: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	वर्तमान वित्तीय वर्ष: 2022-23	कुल	वित्तीय वर्ष: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	चालू वित्तीय वर्ष: 2022-23	कुल
1	असम	-	-	139.45	-	139.45	10.02	4.63	-	-	14.65
2	छत्तीसगढ	145.67	326.70	-	-	472.37	15.91	15.67	3.89	-	35.47
3	झारखंड	135.22	37.37	-	-	172.59	5.00	-	1.88	-	6.89
4	कर्नाटक	663.21	253.40	109.72	-	1,026.33	52.00	18.23	7.37	-	77.60
5	मणिपुर	-	65.81	-	-	65.81	0.86	0.30	-	-	1.16
6	राजस्थान	143.91	521.55	-	-	665.46	8.60	3.90	-	1.75	14.25
	कुल	1,088.01	1,204.83	249.17	-	2,542.01	92.39	42.72	13.14	1.75	150.01